नई दिल्ली, मंगलवार 27 जून, 2017
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

बधाई हो मोदीजी

मोदीजी को बधाई। इसलिए नहीं कि वे एक बार फिर अमरीका पहुंच गए हैं, एक बार फिर वहां के बड़े व्यापारियों को भारत में निवेश का न्यौता दे रहे हैं, एक बार फिर मोदी-मोदी के नारों से मुग्ध होकर जनता को यह बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने अपनी ताकत का एहसास किस कदर करवाया है, एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अमरीका में अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की है। उन्हें बधाई इसलिए भी नहीं कि आज ईद है। बल्कि इसलिए कि वे और उनका दल, उनके साथी, उनकी मातृ संस्था जिस सपने को हकीकत में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे, वह आज सच हो चुका है। अंग्रेजों के बारे में सुनते आए थे कि फूट डालो और राज करो की चाल चलकर उन्होंने भारत को इतने बरसों तक गुलाम बनाया। अंग्रेज जब भारत से गए, तब विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बहुत से लोग सीमा के आर-पार गए, दंगे-फसाद हुए, निर्दोषों की जानें गईं, विभाजन का दर्द लंबे समय तक सालता रहा। लेकिन फिर भी भारत अपनी अनूठी पहचान के साथ जीता रहा, आगे बढ़ता रहा। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि तब हमारे पास नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, डा.अंबेडकर और ऐसे ही महान व्यक्तित्वों का नेतृत्व था। इनके आपसी मतभेद थे, लेकिन उनसे ऊपर उठकर ये देशहित के लिए सोचते थे। देशहित माने सभी धर्मों, वर्गों, जातियों और संप्रदायों के लोगों को साथ लेकर चलना। एक की खातिर दूसरे का हित हनन न हो, इसका ख्याल रखना। हमारा संविधान ऐसी ही दूरदृष्टि और विराट सोच रखने वालों की देन है। आज ये सब बातें प्रवचननुमा, भाषणों के लिए उपयुक्त लग सकती है। लेकिन यह हकीकत है कि अगर हमारे संविधान का रक्षाकवच न होता तो अल्पसंख्यकों, गैरहिंदुओं की दुर्दशा हो जाती। क्योंकि तब जनसंघ की विचारधारा हावी होती। विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय आदि की सोच भारत के आजाद होते ही लागू हो जाती। सावरकर चाहते ही थे कि पूरी राजनीति का हिंदूकरण हो। तो मोदीजी को अब बधाई इसलिए कि सावरकर की सोच उनके शासन में पूरी हो गई है। सौ प्रतिशत न सही, लेकिन भारत में राजनीति का हिंदूकरण इतना हो ही चुका है कि मुसलमान अब डर कर रहने लगा है। आजाद भारत में एक कौम को दूसरी कौम के खिलाफ खड़ी करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा पूरी तरह सफल हो गई है। देश के बड़े तबके में मुसलमानों के लिए अजीब द्वेष पैदा हो चुका है, जो पहले कभी नहीं था। संघ इसके लिए न जाने कब से तैयारी कर रही थी और अब तो खुलकर यह बात सामने है कि कैसे अबोध बच्चों को वह धर्म और संस्कृति की रक्षा का पाठ पढ़ाती है कि वे किसी विधर्मी यानी मुसलमान की जान लेने से न हिचकें। ईसाइयों के खिलाफ उतना जहर फिलहाल नहीं फैलाया जा रहा है, क्योंकि यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया की यात्राएं आगे भी तो करनी हैं। फिलहाल मुसलमानों को ही निशाने पर लिया जा रहा है और इसके लिए अब शायद बहानों की भी दरकार नहीं है।

दादरी में अख़लाक़ को फ्रिज में गोमांस छिपाने के शक में भीड़ ने मार दिया था। अलवर में पहलू ख़ान को इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उस पर गायों की तस्करी करने का शक गाय की रक्षा करने वाली स्वघोषित पुलिस को हुआ, झारखंड के लातेहार में मोहम्मद मज़लूम और इनायतुल्ल खान को इसलिए पेड़ से लटका कर मार डाला गया क्योंकि वो गाय बैल ख़रीद कर ले जा रहे थे और स्थानीय गोरक्षक समिति को शक हुआ कि जानवरों को क़त्ल के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं हैं, सबका उल्लेख यहां संभव नहीं है। इन हत्याओं के पीछे कोई न कोई कारण हत्यारों ने दिया और सरकार ने कभी इसे दुर्घटना कहा, कभी चिंता का दिखावा किया, कभी दुख का फरेब दिखाया, लेकिन ऐसी घटनाएं रूकें, इसके लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। इसलिए अब हिंदुत्व के रक्षक खुद को इतना शक्तिसंपन्न महसूस कर रहे हैं कि ट्रेन में 16 साल के जुनैद और उनके तीन साथियों को केवल इसलिए मारा-पीटा कि वे मुसलमान हैं। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में चार मुस्लिम युवकों की टोपी उछालने, दाढ़ी खींचने, बुरी तरह मारने का कुकर्म होता रहा, उन्हें गोश्त खाने के लिए कोसने और पाकिस्तान चले जाने का फरमान सुनाने का अन्याय होता रहा और ऐसा करने वालों को मौजूद भीड़ उकसाती रही। कोई मदद के लिए सामने नहीं आया क्योंकि जिन्हें पीटा जा रहा था, वे मुसलमान थे। माने विधर्मी थे, माने हिंदुओं से अलग थे। और आज का हिंदू कोई कायर तो है नहीं जो दूसरे धर्म वालों के साथ प्रेमपूर्वक रह ले। आज के हिंदू में अपने धर्म की रक्षा करने की शक्ति है, यह ताकत उसे सत्ता से हासिल हुई है। जुनैद और उनके साथी ईद की खुशियों के लिए सामान खरीद कर ला रहे थे, जब उनके साथ अकारण हिंसा हुई। बुरी तरह घायल जुनैद ने प्लेटफार्म पर ही दम तोड़ दिया। उसके साथी जिंदा हैं, लेकिन उनमें जिंदा रहने का एहसास और ताकत कितनी बची है, यह जरूरी सवाल है। प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कहते हैं, इस बार जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने उनसे मन की बात की है। एक सवाल उनसे किया है कि देश में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? क्या मेरा बेटा भारतीय नहीं था? प्रधानमंत्री मुसलमानों की भीड़ द्वारा हत्या पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे?

प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राओं और भारत के विकास में लग रही मेहनत से थोड़ा वक्त निकालकर इन सवालों के जवाब दीजिएगा। क्योंकि जलालुद्दीन ही नहीं, वे सारे भारतीय, जो राजनीति के हिंदूकरण से बचे हैं, वे भी आपसे जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं।

गोरखालैंड की आर्थिक व्यवहार्यता के बावजूद स्थापना कठिन

दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गौरांग की अगुवाई में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन को दो सप्ताह पूरे हो रहे हैं किन्तु आन्दोलन के थमने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस आन्दोलन के कारण न केवल पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है बल्कि चाय उद्योग पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जहां तक गोरखालैंड की मांग का सवाल है, गोरखालैंड शब्द का पहली बार प्रयोग गोरखा नेशनल लिब्रेशन फ्रंट के नेता सुभाष घीसिंग ने अप्रैल 1980 में करके गोरखालैंड राज्य आन्दोलन को प्रारम्भ किया। वर्तमान में आन्दोलनकारियों द्वारा जिस पर्वतीय हिस्से को लेकर गोरखालैंड बनाने की मांग की जा रही है, उसका कुल क्षेत्रफल 6246 वर्ग किलोमीटर है, उसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और नवनिर्मित कलिम्पोंग जिले के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सेओंग, मिरिक, बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, जयगाव, कालचीनी, कुमारग्राम, मदारीहाट, मालबजार, सिलीगुड़ी और नागरकाटा शामिल हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली लेप्चा, भूटिया, गुरूंग, शेरपा आदि सभी जातियां गोरखालैंड आन्दोलन में हिस्सा ले रही हैं। गोरखालैंड समर्थकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में गोरखाओं की स्थिति दूसरे दर्जे के नागरिक के समान होने से उनके रोजगार और विकास में पिछड़े हैं। पृथक गोरखालैंड राज्य बन जाने पर उनका तेजी से विकास होगा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

सुभाष घीसिंग द्वारा 1986 से 1988 के बीच किए गए आन्दोलन को देखते हुए बहुत उग्र हुए वाममोर्चा सरकार ने 1988 में बीच का रास्ता निकाल कर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल डीजीएचसी का गठन किया तथा सुभाष घीसिंग को उसका अध्यक्ष बनाया गया। किन्तु दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल गोरखा समुदाय की अपेक्षाओं पूरा करने में असफल रहा। सुभाष घीसिंग भी लोकप्रियता खोने लगे। इसलिए जब 2007 में विमल गौरांग की अगुवाई में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गोरखालैंड की मांग के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया तो उसे सुभाष घीसिंग के जीएनएलएफ को छोड़कर पूरे गोरखा समुदाय का पुरजोर समर्थन मिला। 2011 में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से जनमुक्ति मोर्चा से त्रिपक्षीय चर्चा के बाद बनी सहमति के फलस्वरूप अगस्त 2012 में गोरखा हिल काउंसिल के स्थान पर गोरखालैंड टैरेटेरियल एडमिनिस्टेशन जीटीए की स्थापना की गई। स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं भांति कई विभागों के प्रशासकीय कार्य जीटीए को सौंपे गए।

डॉ. हनुमन्त यादव

> केन्द्र की भाजपा सरकार यह जानते हुए भी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भाजपा समर्थक है तथा पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा को जिताया है। लोकसभा चुनाव के चुनावी एजेंडे में पृथक गोरखालैंड के गठन का वादा किया गया था। मोदी सरकार को भय है कि पृथक गोरखालैंड की वजह से दार्जिलिंग खोने के कारण पश्चिम बंगाल के मतदाता उसे कभी माफ नहीं करेंगे, और वह वहां अपने पैर नहीं जमा पाएगी। संभवत: इसी भय से वह लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद पृथक गोरखालैंड राज्य के गठन के बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है। इस प्रकार आर्थिक कारक गोरखालैंड स्थापना के अनुकूल होने के बावजूद राजनीतिक कारक इतने अधिक मजबूत हैं कि इसकी स्थापना कठिन नज़र आ रही है।

गोरखालैंड समर्थक गोरखाओं के छोटे बड़े 13 दल हैं जो 2012 में जीटीए के गठन के बाद भी समय-समय पर गोरखालैंड की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन से उत्साहित होकर अगस्त 2013 में भी आन्दोलन किया था। 12 जून से प्रारम्भ किया गया वर्तमान उग्र आन्दोलन बहुत छोटी सी बात को लेकर प्रारम्भ किया है। हुआ यह कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि अगले सत्र से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बंगाली पढ़ाई जाए। मेरी राय में इसमें गलत कुछ भी नहीं था क्योंकि राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में सरकारी कामकाज बंगाली में किया जा रहा है इसलिए राज्य में नौकरी प्राप्त करने के लिए बंगाली भाषा का ज्ञान जरूरी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एवं अन्य दलों ने इसी बात को मुद्दा बना लिया है कि सरकार गोरखा समुदाय पर बंगाली थोपना चाहती है। आन्दोलन उग्र हो चुका है तथा विमल गोरांग एवं उनके साथियों ने जीटीए से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार वे पृथक गोरखालैंड के अलावा किसी अन्य बिन्दु पर सरकार से चर्चा को तैयार नहीं है न ही वे अन्य कोई विकल्प स्वीकार करेंगे। इस प्रकार वर्तमान आन्दोलन को गोरखा अपनी अंतिम लड़ाई करार दे रहे हैं।

सवाल उठता है कि प्रस्तावित गोरखालैंड में पर्वतीय क्षेत्र और गोरखाओं के द्रुत गति से विकास के लिए वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गोरखालैंड की आर्थिक व्यवहार्यता है कि नहीं और है तो कितनी? उत्तर-पूर्व में वहां की जनजातियों के आन्दोलन की उग्रता के आधार असम से पृथक छोटे राज्यों का गठन किया गया था उनमें से एक भी राज्य की आज तक आर्थिक व्यवहार्यता नहीं हो पाई है। सभी केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता पर आश्रित हैं। दूसरी ओर प्रस्तावित गोरखालैंड राजस्व सम्पन्नता के कारण पूर्णरूप से आर्थिक व्यवहार्यता रखता है। वर्तमान में चाय, पर्यटन तथा जलयोजना से सरकार को 1600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है, फिर भी गोरखालैंड क्षेत्र विकास के मानदंडों पर पिछड़ा है। क्योंकि वह राजस्व गोरखाओं के विकास पर व्यय नहीं किया जा रहा है। चाय और पर्यटन से प्राप्त राजस्व प्रस्तावित गोरखालैंड को राजस्व आधिक्य राज्य बनाने के लिए पर्याप्त हैं। जलीय विकास, नॉन-टिम्बर वनोपज तथा सीमा-पार व्यापार के राजस्व से यह पर्वतीय राज्यों में विकास में प्रथम स्थान रखने वाले सिक्किम के समकक्ष पहुंच जाएगा। गोरखालैंड की भौगोलिक स्थिति सिक्किम से बेहतर है, इसलिए आधुनिक लघु और मझौले उद्योगों की स्थापना से औद्योगीकरण की भी बेहतर संभावनाएं हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार को चाय एवं पर्यटन उद्योग से मिलने वाला राजस्व ही पृथक गोरखालैंड की स्थापना में बाधक बन सकता है। राजस्व घाटा से पीड़ित पश्चिम बंगाल सरकार कभी भी अपने राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत गंवाना नहीं चाहेगी। दार्जिलिंग चाय व पर्यटन पश्चिम बंगाल की दुनिया भर में जो पहचान बनी है, पश्चिम बंगाल में किसी भी दल की सरकार हो वह यह प्रतिष्ठा कभी भी खोना नहीं चाहेगी। केन्द्र की भाजपा सरकार यह जानते हुए भी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भाजपा समर्थक है तथा पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा को जिताया है। लोकसभा चुनाव के चुनावी एजेंडे में पृथक गोरखालैंड के गठन का वादा किया गया था। मोदी सरकार को भय है कि पृथक गोरखालैंड की वजह से दार्जिलिंग खोने के कारण पश्चिम बंगाल के मतदाता उसे कभी माफ नहीं करेंगे, और वह वहां अपने पैर नहीं जमा पाएगी। संभवत: इसी भय से वह लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद पृथक गोरखालैंड राज्य के गठन के बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है। इस प्रकार आर्थिक कारक गोरखालैंड स्थापना के अनुकूल होने के बावजूद राजनीतिक कारक इतने अधिक मजबूत हैं कि इसकी स्थापना कठिन नज़र आ रही है।

एक तीर से कई निशाना साध रहे मोदी

■ उपेन्द्र प्रसाद

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार के राज्यपाल डॉक्टर रामनाथ कोविंद को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर वास्तव में सभी को चौंका दिया है। इसका कारण यह है कि जिन नामों की चर्चा राजग की उम्मीदवारी को लेकर हो रही थी, उनमें यह नाम था ही नहीं। हां, कुछ लोग यह अनुमान अवश्य लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री शायद किसी दलित को इस पद के लिए चुनें। जब दलित राष्ट्रपति की चर्चा होती थी, तो बात आदिवासी राष्ट्रपति की ओर बढ़ जाती थी और तब झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की भी चर्चा होने लगती थी। जब दक्षिण भारत के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बात आती थी, तो लोग वेंकैया नायडू का नाम भी लेने लगते थे, लेकिन जिस दिन भाजपा अमित शाह ने राष्ट्रपति के नाम पर सहमति बनाने वाले तीन लोगों की एक समिति में श्री नायडू का नाम डाला, उसी दिन जाहिर हो गया कि श्री नायडू के उम्मीदवार बनने की संभावना समाप्त हो गई है।

> आखिर श्री कोविंद प्रधानमंत्री की पसंद क्यों बने? इसका एक कारण तो यह है कि मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दलित उनकी पार्टी के साथ जुड़े। दूसरा कारण यह है कि श्री कोविंद उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी वहां भारी जीत हासिल की थी। आगामी चुनाव में भी वहां भाजपा का दबदबा बना रहे, इसके लिए श्री कोविंद का राष्ट्रपति बनना भाजपा के काम आ सकता है। उसका एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 22 फीसदी है और उनमें भाजपा की पैठ बहुत कमजोर है।

भाजपा के कुछ जोशीले कार्यकर्ता आडवानी का नाम भी लेते थे, हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन पर चल रहे मुकदमे के कारण कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन और नजमा हेपतुल्ला तक के नाम पर चर्चा हो जाया करती थी और सुषमा स्वराज के नाम को तो कुछ लोग गंभीरता से लेने लगे थे, लेकिन किसी ने श्री कोविंद के बारे में नहीं सोचा था कि उन्हें भी राष्ट्रपति बनाने की मोदी सोच सकते हैं।

आखिर श्री कोविंद प्रधानमंत्री की पसंद क्यों बने? इसका एक कारण तो यह है कि मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दलित उनकी पार्टी के साथ जुड़े। दूसरा कारण यह है कि श्री कोविंद उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी वहां भारी जीत हासिल की थी। आगामी चुनाव में भी वहां भाजपा का दबदबा बना रहे, इसके लिए श्री कोविंद का राष्ट्रपति बनना भाजपा के काम आ सकता है।

उसका एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 22 फीसदी है और उनमें भाजपा की पैठ बहुत कमजोर है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत की एकमात्र वजह अगड़ी जातियों और ओबीसी का उसे मिला समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी की नज़र गैरजाटव दलित जातियों पर है, जिनका समर्थन वे श्री कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर पा सकते हैं, क्योंकि श्री कोविंद उत्तर प्रदेश के एक गैरजाटव दलित हैं। प्रदेश में गैरजाटव दलितों में यह भावना घर कर गई है कि मायावती के कार्यकाल में सिर्फ जाटवों का सशक्तिकरण हुआ है और उनके इस अहसास का फायदा भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात का चुनावी हित साधने की कोशिश भी श्री कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा कर रही है। श्री कोविंद कोली समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी गुजरात में 20 फीसदी है, हालांकि वह वहां एससी नहीं, बल्कि ओबीसी है। आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने के कारण गुजरात के पटेल भाजपा के विरोधी होते जा रहे हैं और इसकी भरपाई भाजपा वहां कोलियों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर कर सकती है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनावी समीकरण को अपने अनुकूल बनाने के अलावा श्री कोविंद को राष्ट्रपति बनाने के पीछे मोदी की मंशा पार्टी के चेहरे को बदलने की भी है। पार्टी अभी तक अगड़ी जातियों की पार्टी के रूप में जानी जाती है। नरेन्द्र मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर से अगड़ी जातियों के वर्चस्व का ठप्पा समाप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि सत्ता के केन्द्रों पर अगड़ी जातियों के लोग ही भरे हुए हैं और दलित व ओबीसी अपने आपको भाजपा की सत्ता की स्कीम से अलग थलग पा रहे हैं। एक दलित को सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठाकर नरेन्द्र मोदी उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनकी ही पार्टी है। इस कोशिश में मोदी कितना सफल हो पाते हैं, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद महज नुमाइशी होता है और असली सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है और अपने उस अधिकार का इस्तेमाल मोदी ने अभी तक ओबीसी और दलितों के सशक्तिकरण के लिए प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया है।

बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर श्री मोदी ने विपक्षी खेमे में भी बिखराब की स्थिति पैदा करने में सफलता पाई है। राजग के उम्मीदवार की जीत में पहले भी कोई शक नहीं था, क्योंकि उसके पास अपने और कुछ मित्र दलों के साथ राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में पर्याप्त वोट हैं, लेकिन कोविंद के उम्मीदवार बनने से अपने विरोधी खेमे से भी कुछ वोट वह प्राप्त कर सकता है। मायावती अभी से किसी अन्य दलित उम्मीदवार न होने की स्थिति में कोविंद के समर्थन की बात कर रही है, तो नीतीश कुमार भी बिहार के राज्यपाल के प्रति नरमी का रुख अपना रहे हैं। उसके कारण जनता दल(यू) में भी मतभेद पैदा हो सकता है और बिहार का महागठबंधन भी उससे प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के समय बन रही विपक्षी एकता अभी से धराशायी होती दिखाई दे रही है। इस तरह एक तीर से कई निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।

पावन प्रसंग

शाश्वत की खोज अपने अंदर ही करें

'आनंद' आध्यात्म की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है, उसकी अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उच्च मानी जाती है। यों बहिरंग की प्रफुल्लता सर्वसामान्य में भी देखी जाती है, पर वह भौतिकता से जुड़ी होने के कारण अस्थिर होती और घटती-बढ़ती रहती है, लेकिन 'आनंद' आत्मिक होने के कारण चिरस्थायी होता और समस्वर बना रहता है।

आमतौर पर आनंद ओर उत्फुल्लता को एक माना जाता है, किंतु दोनों में जमीन-आसमान जितना अंतर है। जो भेद सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के मध्य है, लगभग वैसा ही फर्क इन दोनों के बीच माना जाना चाहिए। बाह्य वस्तुओं में हमें जहाँ-जहाँ, जब-जब सुख की अनुभूति होती है, वह वस्तुत: हमारे अंतस् के आनंद का ही प्रकाश है, क्योंकि बाहरी उपादानों में सुख कभी होता नहीं। जो होता है, वह मात्र दु:ख है। यदि भौतिक पदार्थ आनंद के स्रोत रहे होते, तो जिस चीज से एक को प्रसन्नता मिलती है, दूसरे के लिए भी वह उत्फुल्लतादायक ही होनी चाहिए थी, पर दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं, वह इसके ठीक विपरीत है देखा जाता है कि जो सामग्री हमारे जीवन में सुख और शाँति लाती है, दूसरे के लिए वही महान दु:ख का कारण बन जाती है। जड़ पदार्थ यदि सचमुच ही प्रसन्नता के उद्गम होते, तो किसी के लिए भी वे विपन्नता के निमित्त नहीं बनते। यदि बनते हैं, तो निश्चय ही समझने में कोई भूल हुई है। इस भूल को समझकर और सुधारकर ही हम उस चिरंतन आनंद को प्राप्त कर सकते है। इस संसार में पदार्थ और चेतना दो प्रधान तत्व है। स्थूल जगत् में पदार्थ ही सर्वोपरि है, जबकि सूक्ष्म जगत् में आत्मा-परमात्मा से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं। दोनों ही अपने-अपने प्रकार के सत्य हैं, पर यह संभव नहीं कि एक से संबंधित सत्य की उपलब्धि दूसरे में की जा सके, न यही शक्य है कि एक का सच दूसरे का पर्याय बने। द्रव्य का गुण आत्मा में ढूंढ़ना निरर्थक है और आत्मा का धर्म पदार्थ और संसार में तलाशना नासमझी। संसार में सौंदर्य भरा पड़ा है। कोई उसको निहारकर गदगद होता रहता है, जबकि दूसरे को उसमें वैसा सुख नहीं मिल पाता। यदि सौंदर्य है, तो इसकी खोज करने वाले प्रत्येक अन्वेषक को इससे सुख मिलना चाहिए, किंतु ऐसा कहाँ होता है? जिस सौंदर्य से, भोग और विलासिता से हमें आनंद मिलता है, उसी से कोई 'बुद्ध' भाग खड़ा होता है, विरागी बन जाता है। यदि सौंदर्य सच्चा है, तो यह विरोधाभास नहीं दिखलाई पड़ना चाहिए। कोई नयनाभिराम सौंदर्य के बीच रहकर भी अतृप्त बना रहता है, जबकि दूसरा घोर नरक जैसी परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख की प्रतीति करता है। आखिर ऐसा क्यों? गहराई से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि जिस शाश्वत संतोष की तलाश हम बाहर करते रहते हैं, वस्तुत: अंदर की वस्तु है। बाहर यदि उसकी अनुभूति होती है, तो वह भी भीतर का ही विस्तार है। जैसे-जैसे हम गहराई में प्रवेश करते चलते है, वैसे-वैसे इस तथ्य की अनुभूति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। हम सुख को बाहरी वस्तुओं में ढूँढ़ना चाहते है। सुख वहाँ है नहीं, इसलिए दु:ख भोगना पड़ता है। इतना जानते-समझते हुए भी व्यक्ति आज संसार में साधनों के पीछे शाँति के लिए भागता फिर रहा है। कोई उसे किसी चीज में खोजने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरा किसी अन्य में अन्वेषण कर रहा है। सभी प्रयत्नशील है, पर आज तक इनमें से कोई भी इस सनातन सुख को उपलब्ध कर पाने में सफल न हो सका।

आश्चर्य तो तब होता है, जब यह विदित होता है कि जिन्हें हम शाँति का पुँज मानते और जिनमें हमें शाँति की तलाश है, वे वास्तव में अशाँत हैं और वे इसकी खोज कहीं अन्यत्र कर रहे है। जिस दिन यह निरर्थक प्रक्रिया बंद होगी, उसी दिन से मनुष्य की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। फिर उसे शाँति और संतोष के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा।

(अखंड ज्योति)

आपके पत्र

देश कब भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा !

बेनामी सौदो की जांच में लालू का परिवार दोषी पाया गया। उसके साथ ही लालू की पुत्री मीसा,दामाद शैलेश कुमार भी शामिल है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अपनी पार्टी और प्रदेश में अच्छी साख है। लालू की पार्टी के कार्यकर्ता लालू के एक इशारे पर सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। लालू ने अपने परिवार और पूर्व सीएम राबडी देवी के नाम पर बेनामी प्रॉपर्टी को आयकर विभाग ने अटैच कर दिया है। इतना ही नहीं अपनी बेटी मीसा और दामाद को भी बेनामी संपति रखने पर कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी हो गई है कि इस का सफाया करना नामुमकिन तो नही है,लेकिन मुश्किल जरूर है। आयकर अधिकारी ने जांच शुरू की उस वक्त वर्तमान मोदी सरकार को दोषी करार देते हुए लालू ने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू के पुत्र तेजस्वी ने भी केंद्र को दोषी बताया था। लालू के परिवार का नाम आयकर विभाग के जांच अधिकारी के हत्थे चढ़ जाने के बाद लालू की बोलती बंद हो गई है। देश में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार मुंहफाडे खड़ा है। देश में नेताओ के मन में देश भावना प्रबल नहीं होगी,तब तक देश आगे नही बढ़ सकता है। लालू राजद के वरिष्ठ मंत्री हैं। उनका नाम चारा घोटाला में भी उछला था। उनको जेल भी हुई थी। आज भी चारा घोटाला का केस अदालत में विचाराधीन है। जब नेता इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका अनुसरण अन्य भी करेंगे। लालू के परिवार में मार्केट वैल्यू करोडों में है और सरकार को कम रकम शो कर भ्रष्टाचार किया है।

-कांतिलाल मांडोत, सूरत

'हिंदी' भाषा का सम्मान हो

सबको हिंदी सीखनी चाहिए यह केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की बात को ट्वीट कर जवाब देते कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 'हिंदी अपनी राष्ट्र भाषा नहीं है। वह भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होने के कारण उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसकी जबरदस्ती किसी पर नहीं होनी चाहिए। हिंदी का नाम लेते ही कुछ लोगों को दिल से अच्छा नहीं लगता। हमेशा अंग्रेजी का ढिंढोरा पीटने वालों को मानो उसकी एलर्जी हो। हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए कुछ न करने वाले उसका होता हुआ प्रचार-प्रसार रोकने के लिए कैसे उतावले होते हैं, उसका उदहारण उनके एक ट्वीट से देखने मिला। जो भाषा देश में सब से अधिक बोली जाती है वह बोलने में क्यों शरमाए? हिंदी भले ही राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल तो राष्ट्रभाषा की तरह ही देश में किया जाता है। देश की मुख्य भाषा का प्रचार रोकने वाले ही उस के दुश्मन होते हं।'सिर्फ काम के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है' यह कहते- कहते उस भाषा ने पूरे देश पर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया है। इस जबरदस्ती के विषय में कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना भारी प्रभाव अंग्रेजी का बढ़ गया है। एक-दूसरे देश की भाषा अपने देश में आती है और उसका उपयोग स्कूल से व्यापार, नौकरी में बड़ी मात्रा में आसानी से होता है। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात है? इस कारण कई छात्र पीछे रह जाते हैं। उन्हें देश के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल बढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी शुरुआत पढ़ाई के माध्यम से कैसे की जा सकती है, उस पर विचार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कर के तो देखिए देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते ही जाएगा। चीन, जापान अपनी भाषाओं का इस्तेमाल शिक्षा सहित कारोबार में करते हैं और उसका नतीजा क्या है, वह पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा बदलाव लाने की दिल से इच्छा होनी चाहिए। उस के बाद देखिए भारत का बच्चा देश की प्रगति के लिए अपना योगदान प्रदान करने के लिए तैयार रहेगा। अंग्रेजी के साथ आए उस के गलत विचारों ने देश की सभ्यता, संस्कृति को बिगाड़ दिया है। हिंदी पर आपत्ति जताने वाले इस विषय पर कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि हिंदी के लिए उन के मन में सम्मान ही नहीं होता। उचित काम के लिए कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे आगे बढ़ाने दे। फिर चाहे वह भाषा हो या व्यक्ति।

जयेश राणे, मुंबई, महाराष्ट्र

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in